Insurance:

Discussions on the Insurance sector related to the absolute and relative amounts of:

— the minimum paid up capital requirement of rupees one billion recommended by the Malhotra Committee;

— the maximum promoter equity participation of 40 per cent;

— and the anticipated mandated investments new participants in this sector were likely to be asked to maintain.

On each of these issues it was felt that, given the size and nature of the Indian market, and the fact that a policy decision regarding government borrowings being made at market rates had already been taken, the recommendations themselves were understandable. In addition, some flexibility was available with regard to each of the above, inbuilt into the policy recommendations currently pending before the government for approval. These issues were hence something that were likely to be evolved gradually in the long run.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उठाए गए घाटे

3379. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में घाटा होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन कारणों को दूर किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो घाटे को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(घ) क्या इस क्षेत्र के कर्मचारियों की लापरवाही और उनके कदाचार के कारण भी घाटा हो रहा हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : (क) कारोबार की कम मात्रा, अनुपयोज्य आस्तियों का उच्च प्रतिशत और कर्मचारियों की अत्याधिक संख्या घाटों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक है। विवेकपूर्ण मानदण्डों को लागू किये जाने से परिणामस्वरूप कुछ बैंकों को प्रावधान संबंधी अधिक अपेक्षाओं और आय की पहचान के कारण हानि भी उठानी पड़ी थी ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों पर अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करने और अनुपयोज्य आस्तियों को सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने के लिए जोर देता रहा है । बैंकों ने अनिष्पादित अग्रिमों की वसूली की अलग से निगरानी के लिए एक महाप्रबन्धक की निगरानी में प्रधान कार्यालयों में "वसूली कक्षों" की स्थापना की है।

(घ) और (ङ) कुछ कर्मचारियों की लापरवाही और कदाचार से भी बैंकों को घाटा होता है। बैंक इसके लिए निवारक और दंडात्मक दोनों ही उपाय करते हैं।

कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता

3380. **श्री आर मोहम्मद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का भी आंकलन किया है ताकि वे प्रति-हैक्टेयर अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए आदानों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने धन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?